



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 11—दिसम्बर 17, 2010 (अग्रहायण 20, 1932)

No. 50]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 11—DECEMBER 17, 2010 (AGRAHAYANA 20, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	1841	प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1141	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	7	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2301	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 3471
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... *		भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... *		भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट..... *		भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 9121
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... *		भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 1765
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1841	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1141	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2301	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3471
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	9121
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1765
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-110015, दिनांक 16 नवम्बर 2010

सं. एफ.-10-4/2009 यू.-3 ए-—जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यह उल्लेख किया गया है “केन्द्र सरकार, आयोग की सलाह पर, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि उच्चतर शिक्षा की कोई संस्था, विश्वविद्यालय के अलावा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम विश्वविद्यालय होगा तथा उक्त घोषणा कर दिए जाने के बाद इस अधिनियम के समस्त प्रावधान उक्त संस्था पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वह धारा 2 के खंड (च) के निहितार्थ एक विश्वविद्यालय है”;

2. और जबकि, केन्द्र सरकार को जनवरी, 2009 में एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (एसआरएम विश्वविद्यालय), जो एक सम विश्वविद्यालय संस्था है, से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें परिसर से बाहर (ऑफ कैम्पस) केन्द्र खोलने के लिए अनुमोदन प्रदान करने तथा इसके द्वारा एसआरएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, इरुंगलूर (तिरुचिरापल्ली) और इरुंगलूर (तिरुचिरापल्ली) स्थित चेन्नई कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल को इसके विस्तार में शामिल करने का अनुरोध किया गया था;

3. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत यथा अपेक्षित आयोग की सिफारिशों को प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव को 03.03.2009 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भेजा गया था;

4. और जबकि, सरकार ने 04.06.2009 को सम विश्वविद्यालय संस्थाओं की पुनरीक्षा करने का आदेश दे दिया, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा गठित पुनरीक्षा समिति द्वारा एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, सम विश्वविद्यालय संस्था, को सारणी-II (द्वितीय श्रेणी) में रखा गया अर्थात् संस्था में कुछ पहलुओं की दृष्टि से कमियां पाई गईं जिन्हें अपने को प्रथम श्रेणी में लाने के लिए और सम विश्वविद्यालय संस्था बने रहने के लिए तीन वर्ष की अवधि के दौरान दूर करना आवश्यक था;

5. और जबकि, पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट सरकार द्वारा सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई थी और इसलिए, ऐसी सम विश्वविद्यालय संस्था के विस्तार में और संस्थाओं को शामिल करने से इसका शैक्षिक स्तर खराब हो जाएगा;

6. और जबकि, सम विश्वविद्यालय संस्थाओं की पुनरीक्षा संबंधी मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है। [विप्लव शर्मा बनाम भारत सरकार रिट याचिका (सी) 2006 की 142];

7. और जबकि, दिनांक 30.09.2009 के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें केन्द्र सरकार को दिनांक 05.10.2009 को प्राप्त हुई थीं तथा सम विश्वविद्यालय संस्थाओं के संबंध में यूजीसी के दिशा-निर्देश (2000) के अन्तर्गत सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद सरकार द्वारा टिप्पणियां दिनांक 14.12.2009 को यूजीसी को भेजी गई थीं जिनमें विचाराधीन सम विश्वविद्यालय संस्था से स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया गया था, जिसमें इसके प्रस्तावित कैम्पस से बाहर के केन्द्रों में छात्रों का प्रवेश शामिल था;

8. और जबकि, यूजीसी ने सम विश्वविद्यालय संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया स्पष्टीकरण अंग्रेषित कर दिया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि तिरुचिरापल्ली स्थित चेन्नई मेडिकल कॉलेज को तमिलनाडु डॉ. एमजीआर चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया गया था तथा तिरुचिरापल्ली स्थित उक्त मेडिकल कॉलेज ने 2009-10 के सत्र में छात्रों को प्रवेश दिया;

9. और जबकि, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मद्रास उच्च न्यायालय में चला गया (डब्ल्यू पी 10952/2010) तथा माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 15.06.2010 के आदेश के द्वारा सरकार को निदेश दिया कि यदि प्रार्थी का आवेदन पत्र सही है तो विचाराधीन संस्थान को तिरुचिरापल्ली स्थित इसके कैम्पस से बाहर के केन्द्रों को चालू करने के लिए अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान करे;

10. और जबकि, सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के ऊपर उल्लिखित आदेश के विरुद्ध अपील कर दी (डब्ल्यू पी 1982/2010) तथा माननीय उच्च न्यायालय ने अपील के संदर्भ में अपने 22.09.2010 के आदेश के द्वारा अपने आदेश में संशोधन कर दिया तथा सरकार को विचाराधीन सम विश्वविद्यालय संस्था के आवेदन पत्र पर, जिसमें कैम्पस से बाहर केन्द्र शुरू करने के लिए अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार विचार करे तथा आदेश की तारीख से चार सप्ताह के अंदर निर्णय लिया जाए;

11. और आगे जबकि, यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम 26.05.2010 से लागू हो गए हैं तथा विनियम के अनुच्छेद 23 में यह शर्त लगाई गई है कि सभी लंबित प्रस्ताव, आवेदक सम विश्वविद्यालय संस्था के विस्तार में कैम्पस से बाहर के केन्द्रों को शामिल करने सहित, इन विनियमों के द्वारा शासित होंगे;

12. और जबकि, यूजीसी ने अपनी सिफारिशें 09.11.2010 को भेजी हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि विचाराधीन सम विश्वविद्यालय संस्था से तिरुचिरापल्ली स्थित इसके कैम्पस से बाहर के

केन्द्रों को शामिल करने के लिए नए सिरे से आवेदन करने के लिए कहा जाए क्योंकि आयोग ने 27.09.2010 को यह निर्णय लिया है कि तिरुचिरापल्ली स्थित इसके कैम्पस से बाहर के केन्द्रों को शामिल करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी के प्रस्ताव सहित सभी प्रस्तावों पर यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम 2010 के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

13. अतः अब, उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद सरकार एतद्वारा यूजीसी की दिनांक 09.11.2010 की सिफारिश को स्वीकार करती है और तदनुसार, सम विश्वविद्यालय संस्था यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार एसआरएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी और चेन्नई मेडिकल कॉलेज, दोनों इरुंगलूर (तिरुचिरापल्ली) स्थित, को अपने विस्तार में शामिल करने के लिए नए सिरे से आवेदन करे।

14. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सुनिल कुमार
अपर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

संकल्प

सं. ई-11012/3/2009-रा.भा.--संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के दिनांक 7 अगस्त, 2006 के संकल्प संख्या ई. 11012/7/06-राजभाषा का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार एतद्वारा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का निम्न प्रकार पुनर्गठन करती है :--

I गठन

1. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अध्यक्ष
 2. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री उपाध्यक्ष
- गैर-सरकारी सदस्य
- संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित
3. चौधरी लाल सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य
 4. श्री हरिन पाठक, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य
 5. श्री बी. के. हरिप्रसाद, संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य
 6. श्री गंगा चरण, संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य
- संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित
7. श्री अशोक अर्गल, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य
 8. मोहम्मद अमीन, संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा नामित

9. प्रो. अनन्तराम त्रिपाठी, प्रधान मंत्री, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, डाकघर-हिन्दी नगर, वर्धा-442003 (महाराष्ट्र) सदस्य
- केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् द्वारा नामित
10. श्री दर्शन सिंह, ई.सी.-138, माया एन्क्लेव, जेल रोड, हरि नगर, नई दिल्ली-110064 सदस्य
- राजभाषा विभाग द्वारा नामित
11. श्री शिव शंकर गुप्ता, बी 2/17, फेज-II, अशोक विहार, नई दिल्ली-110052 सदस्य
 12. श्री राजेश कपूर (राजा), 32/5, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 सदस्य
 13. श्री सुनील बैसोया, पी-6, पिलंजी गांव, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023 सदस्य
- दूरसंचार विभाग द्वारा नामित
14. प्रो. (डॉ.) कृष्ण कुमार गोस्वामी, 1764, औट्रूम लाईन्स, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 सदस्य
 15. प्रो. (डॉ.) टी. आर. भट्ट, निवास "प्रज्ञाश्री", छठा क्रॉस, कल्याण नगर, धारवाड (कर्नाटक)-580007 सदस्य
 16. डॉ. गजभान मुकुट शर्मा, ओ/34, द्वितीय तल, न्यू महावीर नगर, बाहरी रिंग रोड, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018 सदस्य
 17. श्री राघवेन्द्र नाथ द्विवेदी, रेजिडेंट एडिटर, महानगर मीडिया नेटवर्क प्रा. लि., 204-डी विंग, शिव शक्ति दर्शन चन्दन पार्क, जसल पार्क के समीप, भायंदर (पूर्व), जिला-थाणे-410105 सदस्य
- सरकारी सदस्य
- राजभाषा विभाग
18. सचिव सदस्य

19. संयुक्त सचिव	सदस्य	V यात्रा और अन्य भत्ते
दूरसंचार विभाग		
20. सचिव, दूरसंचार	सदस्य	
21. सदस्य (सेवाएं)	सदस्य	
22. सदस्य (वित्त)	सदस्य	
23. सदस्य (प्रौद्योगिकी)	सदस्य	
24. अपर सचिव (दूरसंचार)	सदस्य	
25. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई, बैंगलूर।	सदस्य	
26. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल, नई दिल्ली।	सदस्य	
27. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएसएनएल, नई दिल्ली।	सदस्य	
28. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एमटीएनएल, नई दिल्ली।	सदस्य	
29. कार्यकारी निदेशक, सी-डॉट, नई दिल्ली।	सदस्य	
30. वरिष्ठ उप महानिदेशक, टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेन्टर, नई दिल्ली।	सदस्य	
31. संयुक्त सचिव (प्रशासन)	सदस्य-सचिव	

II समिति का कार्य

इस समिति का कार्य भारत के संविधान में राजभाषा के संबंध में की गई व्यवस्था, राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, केन्द्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन तथा दूरसंचार विभाग और उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों/उपक्रमों के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में सलाह देना है।

III समिति का कार्यकाल

समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगा। संसद सदस्य, जो इस समिति के सदस्य हैं, सदन भंग होने अथवा उनका कार्यकाल समाप्त होने पर या अन्यथा सदन का सदस्य न रहने पर, समिति के सदस्य नहीं रहेंगे। समिति में स्थान खाली होने पर यदि किसी व्यक्ति को सदस्य नामित किया जाता है तो वह शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा। विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

IV सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। तथापि, आवश्यकता पड़ने पर समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

V यात्रा और अन्य भत्ते

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 03 फरवरी, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-II/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों में नामित 15 गैर-सरकारी सदस्यों में 06 संसद सदस्य होते हैं, अतः यात्रा/दैनिक भत्ता प्रावधान को अधिक स्पष्ट करते हुए निम्न प्रावधान किया जाता है :--

(क) समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

(ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-II/20034/04/86-रा.भा.(क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और मंत्रिमंडल कार्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालय, नई दिल्ली को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुधा श्रोत्रिय
संयुक्त सचिव

दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. ई-11012/3/2009-रा.भा.--प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :--

1. समिति के सभी सदस्य।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
3. सभी राज्य सरकार/संघशासित प्रदेश।
4. संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
6. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के निजी सचिव।
7. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के निजी सचिव।
8. योजना आयोग, नई दिल्ली।
9. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
10. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
11. राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।

12. सचिव, दूरसंचार के प्रधान निजी सचिव।
13. अपर सचिव, दूरसंचार के प्रधान निजी सचिव।
14. सभी दूरसंचार उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
15. सभी प्रशासनिक कार्यालयों के प्रमुख।
16. दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) के सभी अधिकारी/अनुभाग।
17. केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्, एक्स. वाई.-68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-23।
18. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, डाकघर-हिंदी नगर, वर्धा-442003 (महाराष्ट्र)।

रमेश चन्द्र शर्मा
संयुक्त निदेशक (रा. भा.)

श्रम और रोजगार मंत्रालय
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय
नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 2010

सं. डीजीईटी-19/31/2010-सीडी--श्रम और रोजगार मंत्रालय (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय), नई दिल्ली के दिनांक 21/24 अगस्त, 1956 के संकल्प संख्या टीआर/ईपी-24/56 (24 अक्टूबर, 2007 तक संशोधित) में आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (पैरा-5) के संघटन को इसके बाद दिनांक 04.11.2010 से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा।

परिषद् का संघटन :--भारत सरकार द्वारा परिषद् का पुनर्गठन किया गया है और इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :--

(क)	केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री	अध्यक्ष
(ख)	श्रम और रोजगार राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
(ग)	भारत सरकार, श्रम और रोजगार के सचिव	सदस्य
(घ)	रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक/संयुक्त सचिव, सदस्य श्रम और रोजगार मंत्रालय	
(ङ)	वित्तीय सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
(च)	उप-महानिदेशक (प्रशिक्षण)	सदस्य
(छ)	उप-महानिदेशक (शिक्षुता प्रशिक्षण)	सदस्य

और निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि :

- (i) तकनीकी शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- (ii) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- (iii) अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय
- (iv) वस्त्र मंत्रालय

जहां तक हो सकेगा, प्रतिनिधि तकनीकी अधिकारी होंगे।

- (ज) आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, नागालैण्ड व त्रिपुरा राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों (शिक्षुता प्रशिक्षण योजना से संबंधित राज्य निदेशक) से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि।
- (झ) भारत सरकार द्वारा नियोक्ता संगठनों के नामित किए जाने वाले तीन प्रतिनिधि।
- (ञ) भारत सरकार द्वारा कामगार संगठनों से नामित किए जाने वाले तीन प्रतिनिधि।
- (ट) भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक और विद्वान निकायों से नामित किए जाने वाले पांच प्रतिनिधि।
- (ठ) भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से नामित किया जाने वाला एक प्रतिनिधि।
- (ड) भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले पांच विशेषज्ञ।
- (ढ) भारत सरकार द्वारा अनु. जाति तथा अनु. जनजाति प्रत्येक से नामित किया जाने वाला एक प्रतिनिधि।
- (ण) भारत सरकार द्वारा महिला संगठन से नामित किया जाने वाला एक प्रतिनिधि।
- (त) निदेशक, प्रशिक्षण, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय श्रम और रोजगार मंत्रालय-सदस्य सचिव।

अनिल स्वरूप
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-110115, the 16th November 2010

No. F. 10-4/2009-U-3A—Whereas Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 states "The Central Government may, on the advice of the Commission, declare by notification in the Official Gazette, that any institution for higher education, other than a University, shall be deemed to be a University for the purposes of this Act, and on such a declaration being made, all the provisions of this Act shall apply to such institution as if it were a University within the meaning of clause (f) of section 2".

2. And whereas, a proposal was received by the Central Government in January 2009 from SRM Institute of Science & Technology (SRM University), an institution deemed to be university, seeking approval for opening of off-campus centres and thereby seeking inclusion of SRM College of Engineering & Technology, Irungalur (Tiruchirapalli) and Chennai Medical College & Hospital, Irungalur (Tiruchirapalli) under its ambit;

3. And whereas, the proposal was sent to University Grants Commission on 3.3.2009 seeking the Commission's recommendations as required under the provisions of Section 3 of the UGC Act, 1956;

4. And whereas, the Government ordered a review of the institutions deemed to be universities on 04.06.2009 wherein SRM Institute of Science & Technology, an institution deemed to be university, was placed in Table-II (second category), i.e., institutions found to be deficient in some aspects which need to be rectified over a three year period for them to transit into the first category for their continuation as institutions deemed to be universities, by the Review Committee constituted by the Government;

5. And whereas, the Report of the Review Committee was accepted, in principle, by the Government and therefore, bringing further institutions under the ambit of such an institution deemed to be university would weaken its academic standard;

6. And whereas, the matter regarding the review of institutions deemed to be universities is sub judice in the Supreme Court of India [Viplav Sharma Vs. UoI WP (C) 142 of 2006];

7. And whereas, the recommendations of the University Grants Commission (UGC) in the matter dated 30.09.2009 were received by the Central Government on 05.10.2009 and after careful examination under the UGC Guidelines (2000) in respect of institutions deemed to be universities, observations were communicated by the Government to the UGC on 14.12.2009 seeking clarifications from the institution deemed to be university in question including admission of students in the proposed off-campus centres thereof;

8. And whereas, UGC forwarded to the Central Government the clarification provided by the institution

deemed to be university wherein it was mentioned inter alia that the Chennai Medical College at Tiruchirapalli was affiliated to Tamil Nadu Dr. MGR Medical University and that the Medical College admitted students in the academic session 2009-2010;

9. And whereas, SRM Institute of Science and Technology approached the Madras High Court [WP No. 10952/2010] and the Hon'ble High Court vide its order dated 15.06.2010 directed the Government to grant approval/sanction to the institution in question for starting its off-campus centres at Tiruchirapalli, if the application of the petitioner was in order;

10. And whereas, the Government appealed against the aforementioned order of the Madras High Court [WA No. 1982/2010] and the Hon'ble High Court was pleased to modify its order, vide its order in Appeal dated 22.09.2010 and directed the Government to consider the application of the institution deemed to be university in question seeking approval/sanction to start the off-campus centres in accordance with Rules and Regulations of the University Grants Commission and take a decision within four weeks from the date of the order;

11. And further whereas, the UGC (Institutions deemed to be universities). Regulations have already come into force with effect from 26.05.2010 and Regulation 23 therein stipulates that all pending proposals, including those seeking inclusion of off-campus centres under the ambit of the applicant institution deemed to be universities, shall be governed by these Regulations;

12. And whereas, UGC has sent its advice to the Central Government on 09.11.2010 stating inter alia that the institution deemed to be university in question may be asked to apply afresh for inclusion of its proposed off-campus centres at Tiruchirapalli in accordance with the decision of the Commission on 27.09.2010 that all proposals, including the present proposal from SRM Institute of Science & Technology seeking approval for inclusion of its off-campus centres, viz., SRM College of Engineering & Technology and Chennai Medical College & Hospital, at Tiruchirapalli, should be processed as per the UGC (Institutions deemed to be universities) Regulations, 2010;

13. Now, therefore, in view of the above circumstances and in terms of the provisions of Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, after considering all relevant facts, hereby accepts the advice of UGC dated 09.11.2010. Accordingly, the institution deemed to be university may apply afresh for inclusion of SRM College of Engineering & Technology and Chennai Medical College, both located at Irungalur (Tiruchirapalli), under its ambit, in accordance with the UGC (Institutions deemed to be universities) Regulations, 2010.

14. This order issues with the approval of the Competent Authority.

SUNIL KUMAR
Additional Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION
TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi, the 21st October 2010

No. E-11012/3/2009-O.L.—In supersession of the Department of Telecom, Ministry of Communications & I.T., Resolution No. E. 11012/7/06-O.L. dated 7th August, 2006, the Government of India hereby reconstitutes the Hindi Salahkar Samiti of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications and Information Technology as under :—

I. Composition

- | | |
|--|---------------|
| 1. Minister of Communications & Information Technology | Chairman |
| 2. Minister of State for Communications & I.T. | Vice Chairman |

Non-Official Members

Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

- | | |
|--|--------|
| 3. Chaudhary Lal Singh, M.P. (Lok Sabha) | Member |
| 4. Shri Haren Pathak, M.P. (Lok Sabha) | Member |
| 5. Shri B. K. Hariprasad, M.P. (Rajya Sabha) | Member |
| 6. Shri Ganga Charan, M.P. (Rajya Sabha) | Member |

Nominated by the Committee of Parliament on Official Language

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 7. Shri Ashok Argal, M.P. (Lok Sabha) | Member |
| 8. Mohammed Amin, M.P. (Rajya Sabha) | Member |

Nominated by Rashtrabhasha Prachar Samiti

- | | |
|---|--------|
| 9. Prof. Anantram Tripathi, Pradhan Mantri, Rashtrabhasha Prachar Samiti, P.O.-Hindi Nagar, Vardha-442003 (Maharashtra) | Member |
|---|--------|

Nominated by Kendriya Sachavalaya Hindi Parishad

- | | |
|---|--------|
| 10. Shri Darshan Singh, E.C.-138, Maya Enclave, Jail Road, Hari Nagar, New Delhi-110064 | Member |
|---|--------|

Nominated by the Department of Official Language

- | | |
|--|--------|
| 11. Shri Siv Shanker Gupta, B-2/17, Phase-II, Ashok Vihar, Delhi-110052 | Member |
| 12. Shri Rajesh Kapoor (Raja), 32/5, Pashchimi Patel Nagar, New Delhi-110008 | Member |

- | | |
|---|--------|
| 13. Shri Sunil Baisoya, P-6, Pilanji Gaon, Sarojini Nagar, New Delhi-110023 | Member |
| Nominated by the Department of Telecommunications | |

- | | |
|--|--------|
| 14. Prof. (Dr.) Krishan Kumar Goswami, 1764, Outram Lines, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009 | Member |
|--|--------|

- | | |
|---|--------|
| 15. Prof. (Dr.) T.R. Bhat, Residence: "Prajnashree", 6th Cross, Kalyan Nagar, Dharwad (Karnatak)-580007 | Member |
|---|--------|

- | | |
|---|--------|
| 16. Dr. Gajbhan Mukut Sharma, O/34, 2nd Floor, New Mahabir Nagar, Outer Ring Road, Vikashpuri, New Delhi-110018 | Member |
|---|--------|

- | | |
|---|--------|
| 17. Sh. Raghavendra Nath Dwivedi, Resident Editor, Mahanagar Media Network Pvt. Ltd. 204, D-Wing, Shiva Shakti Darshan Chandan Park, Near Jasal Park, Bhayander (East), Distt. Thane-410105 | Member |
|---|--------|

Official Members

Department of Official Language

- | | |
|---------------------|--------|
| 18. Secretary | Member |
| 19. Joint Secretary | Member |

Department of Telecommunications

- | | |
|---|------------------|
| 20. Secretary (Telecom.) | Member |
| 21. Member (Services) | Member |
| 22. Member (Finance) | Member |
| 23. Member (Tech.) | Member |
| 24. Additional Secretary (Telecom.) | Member |
| 25. Chairman & Managing Director, I.T.I. Bangalore | Member |
| 26. Chairman & Managing Director, T.C.I.L., New Delhi | Member |
| 27. Chairman & Managing Director, B.S.N.L., New Delhi | Member |
| 28. Chairman & Managing Director, M.T.N.L., New Delhi | Member |
| 29. Executive Director, C-DoT, New Delhi | Member |
| 30. Sr. DDG, Telecom, Engineering Centre, New Delhi | Member |
| 31. Joint Secretary (Admn.) | Member-Secretary |

II. FUNCTIONS OF THE SAMITI

Functions of the Samiti will be to render advice to the Government in regard to the implementation of the provisions

relating to Official Language contained in the Constitution, Official Language Act and Rules and Policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Department of Official Language and also in regard to the progressive use of Hindi in the Department of Telecommunications and its attached, Subordinate, Corporate Offices.

(iii) TENURE OF THE SAMITI

The tenure of the Samiti will be three years from the date of its constitution, Members of Parliament, who are members of the Samiti, shall cease to be members of the Samiti on the dissolution of the House or on expiry of their term or otherwise ceasing to be members of the House. If a vacancy arises in the Samiti, the member nominated against that vacancy shall hold office for the remaining period. Under special circumstances the tenure of the Samiti may be curtailed or extended.

IV. GENERAL

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi. However, it may hold its meetings at any outstations also, if necessary.

V. TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES

The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, vide their Office Memorandum No. II/20034/04/2005-OL(Policy-2) dated 3rd February, 2006 has stated that as the 15 Non-Official members include 6 Members of Parliament, nominated in the Hindi Salahakar Samitis constituted by Central Ministries/Department, so the provision regarding Travelling/Daily Allowance is made more elaborate in the following manner :—

- (a) The members of Parliament nominated in the Samiti will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance as per the provisions in the "Members of Parliament (Salary, Allowance and Pension) Act, 1954", amendments issued from time to time and rules made thereunder.
- (b) Travelling Allowance and Daily Allowance to other Non-Official Members of the Samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language OM No. II/20034/04/86-OL(A-2) dated 22nd January, 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, all Ministries and Deptts. of the Govt. of India, President Secretariat, Prime Minister Office, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

Ordered also that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SUDHA SHROTRIA
Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT & TRAINING

New Delhi, the 19th November 2010

No. DGE&T-19/31/2010-CD—In partial modification of Ministry of Labour & Employment (Directorate General of Employment & Training), New Delhi. Resolution No. TR/EP-24/56 dated 21st/24th August 1956 (amended upto 24th October, 2007) the composition of National Council for Vocational Training (Para-5) shall hereinafter stand amended as under w.e.f. 4.11.2010 :

Composition of the Council : The Council is reconstituted by the Government of India and it consists of the following members :—

- | | |
|---|---------------|
| (a) Union Minister for Labour & Employment | Chairman |
| (b) Minister of State for Labour & Employment | Vice Chairman |
| (c) Secretary to the Government of India, Labour & Employment | Member |
| (d) Director General Employment & Training/Joint Secretary, M/o Labour & Employment | Member |
| (e) Financial Advisor, M/o Labour & Employment | Member |
| (f) Dy. Director General (Training) | Member |
| (g) Dy. Director General (Apprenticeship Trg.) | Member |

and on representative each of the following :—

- (i) Department of Technical Education, Ministry of Human Resource Development
- (ii) Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology
- (iii) Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
- (iv) Ministry of Textiles

The representatives shall, as far as possible, be Technical Officers.

- (h) One representative each from the State Government/ Union Territory Administrations (State Directors dealing with Craftsmen Training Scheme)—Andhra Pradesh, Assam, Gujarat, Himachal Pradesh, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Kerala,

- Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal, Jammu & Kashmir, Haryana, Bihar, Delhi, Nagaland and Tripura
- (i) Three representatives of Employers Organizations to be nominated by the Government of India
- (j) Three representatives of Workers Organizations to be nominated by the Government of India
- (k) Five representatives of Professional and Learned Bodies to be nominated by the Government of India
- (l) One representative of the All India Council for Technical Education to be nominated by the Government of India
- (m) Five Expert to be nominated by the Government of India
- (n) One representative each of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to be nominated by the Government of India
- (o) One representative of Women Organization to be nominated by the Government of India
- (p) Director of Training, DGE&T M/o Labor & Employment—Member Secretary
- ANIL SWARUP
Jt. Secy.